

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1599

मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा इंडिया परिवार से धन वापस

1599. श्री रवि किशन  
श्री रवीन्द्र कुशवाह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों के धन को वापस करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा;
- (ग) क्या वर्तमान में केवल 10,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या भारी धनराशि जमा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि.) सं. 191/2002 (पिनाक पानी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर की गई अंतरवर्ती याचिका (Interlocutory Application) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि:

*"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.*

*(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the*

*genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."*

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश में अनुसरण में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियां, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन युनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने वैध जमा के रिफंड हेतु दावों की प्रस्तुति हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" <https://mocrefund.crcs.gov.in> नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज-रहित है।

पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमाराशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर प्रोसेस किया जा रहा है। भुगतान सीधा प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है।

ऐसे जमाकर्ता जिनके दावों में पाई गई कमियां के कारण जिन्हें प्रोसेस नहीं किया जा सका था, के दावों की ऐसी कमियों में सुधार करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पुनःप्रस्तुत करने हेतु "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (पुनःप्रस्तुति)" <https://mocresubmit.crcs.gov.in> का शुभारंभ किया गया है।

वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ता को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में 10,000 रुपए तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*